PUNJAB KESARI-DELHI EDITION

05-11-2011

सरकार के लिए अब मजदूर बनेंगे मुसीबत

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (ब्यूरो) : विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार, महंगाई कालाधन आदि मामलों से घिरी सरकार के लिए अब देशभर के असंगठित क्षेत्र के मजदूर मुसीबत बनेंगे। देश के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत करीब 40 करोड़ से ऊपर के असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, एक समान पेंशन व श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराने आदि मांगों को लेकर मजदूरों का बड़ा मजमा लगने जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में देशभर से करीब 3 लाख मजदूर 23 नवम्बर को संसद घेरेंगे। राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की मौजूदगी ही दिल्ली और केंद्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत होगी। ये पहला मौका होगा, जब देश के सभी राज्यों की भागेदारी होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस मौके पर पड़ोसी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत और बी.एम.एस. से जुड़े शत-प्रतिशत कर्मचारी शामिल होंगे, ऐसा संगठन का दावा है। इससे पूर्व 8 नवम्बर को देश के सभी राज्य व जिला मुख्यालयों में जेल भरो आन्दोलन होगा।

-3 लाख मजदूर 23 नवम्बर को घेरेंगे संसद

-8 नवम्बर को देश के सभी राज्यों में होगा जेल भरो आंदोलन

बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री बैजनाथ राय के मुताबिक आय विषमता दूर करने के लिए न्यूनतम वेतन और सर्वाधिक आय में एक और दस का अनुपात करके विषमता की खाई को समाप्त किया जाए, तथा देश का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन घोषित हो। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम पेंशन 3 हजार रुपये महंगाई भत्ते से संबंद्ध करते हुए घोषित किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के मामले में देश का 93 प्रतिशत श्रम बल असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के दायरे से पूरी तरह से वंचित है, इन क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए संगठित क्षेत्र में जहां योजनाएं हैं, उनमें सुधार कर और प्रभावी किया जाए। बैजनाथ शुक्रवार को दोपहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जिले सिंह, महामंत्री ऋषिपाल सिंह, राजिंदर सोनी, किरण कुमार दत्ता आदि मौजूद रहे।